प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 21 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 21 – 28 मई 2018 मूल्य पांच रूपए

पेयजल संकट पर सरकार की गंभीरता सवालों में

शिमला/शैल। इन दिनों पूरे प्रदेश में पेय जल संकट चला हुआ है। इस संकट से कितनी चुभन होती है इसे अभी 25 मई को प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी भोगा है जब उनके शिमला स्थित सरकारी आवास पर पानी खत्म हो गया और रात 11:30 बजे नगर निगम के उप महापौर ने टैंकर भेजकर पानी का प्रबन्ध करवाया। धूमल ने इस आपबीति को जनता के साथ सांझा नही किया है क्योंकि इससे सरकार और निगम के प्रबन्धन की पोल खुल जाती। शिमला के कई भागों में छः छः दिन तक पानी नही मिल रहा है। कनलोग क्षेत्र में सीवरेज का पानी सप्लाई कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये। लेकिन इन निर्देशों पर कसौली कांड में पुलिस कर्मियों के निलम्बन की तर्ज पर कारवाई न करके केवल इन्हें संवदेनशील पदों से ही हटाया गया है। इससे सरकार की चिन्ता और गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि इससे पूर्व सरकार ने पीलिया के लिये दोषी रहे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी अनुमति नही दी है।

लेकिन इससे भी बड़ी संवदेनशीलता तो नगर निगम की महापौर की सामने आयी है जो कि इतने बड़े जल संकट को नज़रअन्दाज करके चीन यात्रा पर चली गयी है। अपने साथ अपने पीए को भी ले गयी है। इस यात्रा की अनुमति सरकार द्वारा ही दी गयी है। लेकिन इसमें सरकार ने उनके पीए को भी साथ जाने की अनुमति कैसे और क्यों दे दी है इसका जवाब निगम में किसी के पास नही है। इस संकट में मेयर की यात्रा इसलिये प्रासांगिक हो जाती है क्योंकि इस समय निगम का आधा प्रशासन तो लोगों के फोन तक नही सुन रहा है। ऐसा इसलिये हो रहा है कि जब शीर्ष प्रशासन को ही शहर की जनता की चिन्ता नही है तो नीचे वालों को क्या होगी।

पानी संकट प्रदेश के दस जिलों में बहुत गंभीर हो चुका है। यह संकट पिछले एक दशक से लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मीयों में पानी के स्त्रोत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर सिरमौर, बिलासपुर और शिमला में पड़ता है। सिरमौर में 29% बिलासपुर में 27% और शिमला में करीब 16% स्त्रोत सूख जाते हैं इसका प्रभाव कांगड़ा में 17% मण्डी में 14% कुल्लु 10% ऊना 8% और हमीरपुर में 5% स्त्रोतों पर पड़ता है। इसके कारण करीब 10% शहरी और 75% ग्रामीण आबादी प्रभावित होती है। यह स्टडी आईपीएच विभाग में उपलब्ध है। इसमें यह चेतावनी भी दी गयी है कि यह संकट हर वर्ष बढ़ता जायेगा और 2009 के बाद यह गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश में इस समय करीब नौ हज़ार पेयजल योजनाएं चल रही हैं। करीब दस हज़ार प्राकृतिक स्त्रोत प्रदेश में उपलब्ध है लेकिन इन सारे स्त्रोतों का रख-रखाव नही हो रहा है। जिन स्त्रोतों से पाईपों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है सरकार का रख -रखाव उन्ही तक सीमित हो कर रह गया है। ऊपर से आईपीएच और लोक निर्माण विभागों में जेई से ऊपर तो स्टॉफ की भर्ती हो जाती है लेकिन निचले स्तर पर जिन कर्मियों ने फील्ड में काम करना होता है उनकी भर्ती नही हो रही है क्योंकि सारा काम ठेकेदारों और आऊट सोर्स के माध्यम से करवाने का चलन हो गया है।

अभी 26 जनवरी को सिंचाई एवम् जन स्वास्थ्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि सरकार 3267 करोड़ की एक बड़ी पेयजल योजना पर काम कर रही है। मुख्यमन्त्री ने भी हरीपुरधार में घोषणा की है कि सरकार 2572 करोड़ पेयजल पर खर्च कर रही है। यदि पिछला 15 वर्षो का रिकार्ड खंगाला जाए तो आईपीएच में हजारों करोड़ की पाईपें खरीदी गयी हैं जो शायद अगले दस वर्षो के लिये पर्याप्त होंगी। हर वर्ष भारी मात्रा में पाईपे खरीदी जा रही हैं। विभाग के सूत्रों के मुताबिक जितनी पाईपें खरीदी जा चुकी हैं उनसे प्रत्येक गांव के प्राकृतिक स्त्रोत से पानी लिफ्ट करके उस गांव को दिया जा सकता था। लेकिन एक गांव के बड़े स्त्रोत से पानी लिफ्ट करके दस बीस गांवो को पानी दे दिया जाता है और इसके कारण शेष गांव के स्त्रोत नज़रअन्दाज हो जाते हैं और बिना देखभाल के वह पानी लोप हो जाता है। इसी के साथ प्रकृति के साथ बड़ी योजनाओं के नाम पर जो छेड़छाड़ की जा रही है उसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ रहा है।

अभी सरकार 3267 करोड़ की जिस बड़ी पेयजल योजना पर काम कर रही है उसमें भी समान की खरीद और योजना को कार्यरूप देने में भी सारा पैसा खर्च किये जाने का प्रारूप तैयार किया गया है। योजना बन जाने के बाद उसके संचालन के फील्ड स्टॉफ का प्रबन्धन शायद आऊट सोर्स करने पर छोड़ा जा रहा है। शिमला के लिये कोल डैम से पानी लाने की 400 करोड़ की योजना पिछले पांच वर्षो से सरकारी तन्त्र की लालफीताशाही के कारण व्यवहारिक शक्ल नही ले पायी है। सूत्रों की माने तो कई ठेकेदारो ने इसमें रूचि दिखाई थी जो कि ऊपर के कमीशन की मांग अधिक होने के कारण सफल नही हो पायी है। इस योजना पर अभी भी गंभीरता नही दिखायी जा रही है। यदि सरकार सही में गंभीर होती तो इसमें बाधा बने तन्त्र के खिलाफ कारवाई करके इस योजना पर काम शुरू करवा सकती थी। सरकार ने शिमला के लिये एक जल निगम गठित करने की भी घोषणा की थी लेकिन यह भी अभी तक शक्ल नही ले पायी है।

यही नही शिमला के जल संकट को लेकर तो पहली बार उच्च न्यायालय की बार कौंसिल ने कोर्ट से गैर हाजिर रह कर अपना आक्रोश प्रकट किया। वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिनिधि मण्डल ने पानी को लेकर डीसी को ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि यदि यह व्यवस्था न सुधरी तो यह लोग रिज पर गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठेंगे। शिमला के जल संकट के लिये केवल इसके प्रबन्धन को ही दोषी माना जा रहा है। क्योंकि जो टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है उन टैंकरों में पानी रिज के ही जन भण्डारण से भरा जा रहा है। इससे भण्डारण में नियमित सप्लाई के लिये स्तर नही बन पा रहा है। इससे आम आदमी को पानी मिल नही रहा है और टैंकरों से केवल मन्त्रीयों और शीर्ष नौकरशाही की टंकियां ही भरी जा रही है। शिमला के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की ओर प्रशासन का कितना ध्यान है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बैमलोई के पास एक बड़ा प्राकृतिक स्त्रोत था जिसे एक संस्था टैप करके अपने उपयोग के लिये ले गयी और संबद्ध प्रशासन ऑखे बन्द करके बैठा रहा। इसी तरह की स्थिति कई अन्य स्त्रोंतो के साथ भी हुई जिन्हें कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने स्वार्थ के लिये बन्द करवा दिया है। ऐसा शहर के लिफ्ट एरिया और राम बाज़ार में घट चुका है।

सहकारी बैंको में 938 करोड़ का एनपीए या घपला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में दस बैंक कार्यरत हैं यह बैंक हैं हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक, जोगिन्द्रा सहकारी बैंक, हि. प्र. राज्य सहकारी एवम् ग्रामीण विकास बैंक, कांगड़ा कृषि एवम् सहकारी बैंक, विकास बैंक, शिमला अर्बन सहकारी बैंक, परवाणु अर्बन सहकारी बैंक, मण्डी अर्बन सहकारी बैंक, बघाट अर्बन सहकारी बैंक और चम्बा अर्बन सहकारी बैंक। यह बैंक प्रदेश में सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। इनमें अर्बन सहकारी बैंको को छोड़कर सबमें एमडी/प्रशासक की नियुक्ति प्रदेश सरकार करती है और इस तरह इनके प्रबन्धन में सरकार का सीधा दखल भी रहता है। इस दखल के अतिरिक्त प्रदेश का रजिस्ट्रार सहकारिता तो इन सब बैंकों का एक तरह से नियन्ता ही होता है। इनका पूरा बोर्ड एक तरह से पंजीयक को जवाब देह होता है। ऐसे में इनमें हो रहे हर कार्य के लिये इनके निदेशक मण्डल के साथ ही सरकार भी बराबर की जिम्मेदार रहती है। प्रदेश के यह सहकारी बैंक वाणिज्यक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें केवल राज्य सहकारी बैंक को ही वाणिज्य बैंक का स्तर मिला हुआ है। यह अधिकांश में लोगों की जमा पूंजी के ही सहारे अपना कारोबार करते हैं। कुछ को नाबार्ड से भी निवेश सहायता मिलती है। यह बैंक आरटीआई के दायरे से भी बाहर हैं इसलिये इनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और रजिस्ट्रार सहकारिता पर ही आती है और इसके तहत पंजीकृत हर संस्था को हर वर्ष अपनी आडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देनी होती है।

प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति कितनी गंभीर है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता हैं कि सरकार को वित्तिय वर्ष के आरम्भ में ही 700 करोड़ ऋण लेना पड़ गया है। इस बजट में की गयी घोषणाओ को पूरा करने के लिये सरकार को ग्याहर हजार करोड़ का ऋण लेना पड़ेगा इसका खुलासा बजट दस्तावेजों से हो जाता है यह स्थिति एक गंभीर चिन्ता का विषय बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि सरकार इस बारे में गंभीर नही दिख रही है क्योंकि प्रदेश के सहकारी बैकों का एनपीए 938.27 करोड़ हो गया है। स्वभाविक है कि इन बैकों से यह ऋण प्रदेश के ही लोगो ने लिया है और उसे वापिस नही किया गया। बैंको ने इस ऋण को बसूलने के लिये कोई कड़े कदम उठाने की बजाये इसे एनपीए में डालकर अपनी सीधी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है।

इस पर यह सवाल उठता है कि जब यह ऋण वापिस नही आ रहा था तब बैंक प्रबन्धन से लेकर आरसीएस तक ने क्यों कोई कड़े कदम इसे वसूलने के लिये नही उठाये। क्या ऐसा न करने के लिये कोई राजनीतिक दबाव था या स्वयं बैंको का शीर्ष प्रबन्धन भी इसमें भागीदार था। क्योंकि इतनी बडी रकम को एनपीए की जगह सीधा घपला मानकर इसकी जांच की जानी चाहिये। इसकी जांच जयराम सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि सूत्रों की माने तो बहुत ऋण बिना पात्रता के दिये गये हैं जिनमें कुछ विद्युत परियोजाओं और बड़े हाटलों को फाईनैस किया गया है जो कि वापिस नही आया है।

इस समय प्रदेश के इन दस बैंको में 938.23 करोड़ का एनपीए चल रहा है जिसमें कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक 560.60 करोड़ के साथ पहले स्थान पर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक 250.48 करोड़ के एनपीए के साथ दूसरे नंबर पर है। बैंकिग नियमों के मुताबिक यदि किसी बैंक का एनपीए 15% तक पंहुच जाये तो बैंक को बन्द कर देने तक की चर्चा चल पड़ती है। कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक का एनपीए 14. 87% है। इसमें यदि इसके रिस्क फंडज़ को डाला जाये तो यह निश्चित रूप से बन्द कर दिये जाने के दायरे में आता है। उसी तरह राज्य सहकारी बैंक का एनपीए 4.91% है लेकिन इसके रिस्क फंडज़ 16.92% है। जिसका सीधा अर्थ है कि यह कभी भी एनपीए हो सकते हैं। इस तरह राज्य सहकारी बैंक भी खतरे के उस कगार तक पंहुच चुका है।

यह हैं एनपीए का विवरण

1.	राज्य सहकारी बैंक –	250.48 करोड़ 4.91%
2.	कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक –	560.60 करोड़ 14.87%
3.	जोगिन्द्रा सहकारी बैंक	52.66 करोड़ 15.86%
4.	हि. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक	84.45 करोड़ 20.80%
5.	कांगड़ा कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक –	29.50 करोड़ 24.60%
6.	शिमला अर्बन सहकारी बैंक –	2.04 करोड़ 6.60%
7.	परवाणु अर्बन सहकारी बैंक	6.06 करोड़ 3.3%
8.	मण्डी अर्बन सहकारी बैंक –	1.32 करोड़ 27.98%
9.	बघाट अर्बन सहकारी बैक	20.99 करोड़ 4.5%
10.	चम्बा अर्बन सहकारी बैंक –	0.23 करोड़ 2.55%

प्राकृतिक कृषि प्रणाली को अपनाये किसान:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों का शून्य लागत प्राकृतिक खेती के घटक तैयार करने के तौर – तरीकों को समझने का आह्वान किया है ताकि इसे व्यवहारिक रूप दिया जा सके और अधिक से अधिक लोग इसे अपनाने को आगे आएं।

राज्यपाल मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर के राजकीय महाविद्यालय बासा में कृषि विभाग द्वारा शून्य लागत प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' पर तीन दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे।

वह इस मिशन को राज्य के किसानों तक ले जाना चाहते हैं और उन्होंने प्राकृतिक खेती के इस मिशन को समझने तथा 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार को बधाई दी है। उन्होंने आशा जताई कि राज्य के लोग भावी पीढ़ी के लाभ के लिए इसे अपनाने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घांजीवामृत तथा प्राकृतिक रूप से तैयार किए जा रहे कीटनाशकों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि के उत्पाद न केवल स्वस्थ जीवन के लिए लाभकारी है बल्कि पर्यावरण मित्र भी हैं।

कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती को राज्य में राज्यपाल के कुशल मार्गदर्शन में कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तथा स्वयं उन्होंने प्राकृतिक कृषि के लाभों का व्यवहारिक तौर पर पता लगाने के लिए कुरूक्षेत्र स्थित गुरूकुल का दौरा किया और इसके बाद इस प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा शिविरों को आयोजन किया जा रहा है और पालमपुर के बाद यह दूसरा शिविर है तथा तीसरा सोलन जिले के कण्डाघाट में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुशहाली की ओर यह पहला कदम है तथा इस प्रणाली के क्रियान्वयन से न केवल किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि लोग स्वस्थ जीवन – यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक जागरूकता शिविर है और निकट भविष्य में प्राकृतिक कृषि की जानकारी प्रदान करने के लिए इसी प्रकार के शिविर ग्रामीण स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।

नाचन क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार ने राज्यपाल तथा मंत्री का स्वागत किया और कहा कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की एक आदर्श कृषि प्रणाली को राज्य में पहली बार कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत पांच माह के दौरान नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास गतिविधियां आरम्भ की गई हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों के स्तरोन्नयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

कृषि विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने राज्य में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के कार्यान्वयन के लिए दिशा – निर्देश प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसान बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस प्रणाली का अपनाना आसान है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने में किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग द्वारा अन्य सम्बद्ध विभागों के सहयोग से आयोजित किए जाने वाला यह दूसरा शिविर है।

बच्चों को सुसंस्कारित बनाने में अभिभावक व शिक्षकों की अहम् भूमिका: राज्यपाल

शिमला/शैल। बच्चों को संस्कारित करना और उनमें मानवीय गुणों का समावेश करना अभिभावकों और गुरुजनों की नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि वे बच्चे के सबसे बड़े संरक्षक व मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए बच्चों को अपने अभिभावकों, गुरुजनों तथा बड़ों का आदर – सम्मान करना चाहिए।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत सोलन जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में संभव संस्था द्वारा आयोजित नशा निवारण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि नशाखोरी समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसपर प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करने की आवश्यकता है। नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। यह शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। नशे के आदी व्यक्ति का समाज भी सम्मान नहीं करता है और धीरे – धीरे व्यक्ति में नकारात्मकता आने लगती है जिससे वह अपराधिक प्रवृति का हो जाता है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था विवेक और समझदारी से जीने की आयु है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि माता – पिता को बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए और उनसे दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए ताकि वे कुसंगति में न पड़े। उन्होंने कहा कि अपने अभिभावकों से सम्पर्क तथा गुरुजनों के सानिध्य में रहने से ही सही मार्ग का चयन संभव है। उन्होंने बच्चों को देश के पूर्व राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम तथा अन्य महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि परिश्रम की पराकाष्ठा किशोरावस्था में पड़ जाए तो व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की संपति हैं और उन्हें हर हालत में नशे जैसी बुराई से बचाना है। नशा एक ऐसी समस्या है जो अनेक दूसरी समस्याओं को जन्म देता है और इसके परिणामस्वरूप अपराध बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा को जन्म देता है और परिवार टूटते हैं। आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' तथा स्वच्छता अभियान के अलावा शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के विभिन्न पहलूओं पर भी चर्चा की।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने कुनिहार के समीप शिव गूफा परिसर में जामुन का पौधा रोपकर वन विभाग के पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पाठशाला परिसर में भी पौधारोपण कर विद्यार्थियों को वन संरक्षण का संदेश दिया।

इसके उपरांत, आचार्य देवव्रत ने कुनिहार के विभिन्न स्कूलों के मेधावी छात्र – छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने जैविक कृषि में कार्य कर रहे प्रगतिशील किसानों को भी पुरस्कृत किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER "

Sealed item rate tender on form No. 6&8 for the following works detailed in the table below hereby invited by the Executive Engineer, NH Division, HPPWD, Pandoh on behalf of Governor of Himachal Pradesh from the eligible contractors of appropriate Class registered in HPPWD as per revised enlistment rule so as to reach in his office on 20-06-2018 at 11.00 A.M. The tenders shall be opened on the same date at 11.30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representative who wish to be present. The request for issuing tenders form along with earnest money must reach in his office up to 3.00 P.M. on 18-06-2018 and that tender documents can be had from his office on cash payment noted against each (Non-Refundable) on 19-06-2018 up to 5.00 P.M on any working day. Notice Inviting Tender and other specification and conditions of the tender can be seen by the contractor in the office of the Executive Engineer, NH Division, HPPWD, Pandoh during office hour on any working day.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of form	Time Period of compl-etion	Form No.	Eligibility of contr-actor
1	Metalling/Tarring of shoulders in built up area of Bali Chowki Bazar on Sainj-Luhari-Jalori-Banjar-Aut road NH-305 in Km. 84/270 to 84/520 against OFC deposit.	Rs.7,06,324/-	Rs.14100/-	Rs.350/-	Two Months	6&8	Class C&D enlisted in HPPWD

TERMS & CONDITIONS: - The tender documents shall be sold to only those contractors who fulfill the following terms & conditions as under:-
1. The earnest money as shown against the above work in the shape of National Saving Certificate, Time Deposit account in any Post Office in H.P./FDR of any Scheduled Bank in India duly pledged in the name of the Executive Engineer, NH Division, HPPWD, Pandoh must be accompanied with the application for obtaining tender form. Tender application received without earnest money will summarily be rejected.
2. The contractor should possess the following documents (photo copy to be attached with the application for obtaining the tenders documents):-
(i) latest enlistment/renewal of enlistment orders
(ii) proof of valid registration under the HP GST.
(iii) Permanent Account number (PAN) issued by the Income Tax Department.
3. The contractor should not have more than two works in hand. The detail of executed work/works in hand be supplied at the time of application.
4. The contractor shall have executed similar nature of work at least 40 % of the amount put to tender. The work done certificate and details of work in hand should be signed by an officer not below the rank of Executive Engineer.
5. Conditional and incomplete tender shall be rejected.
6. The Executive Engineer, NH Division, HPPWD, Pandoh reserves the right to accept or reject the tender without assigning any reason.

Adv. No.-0725/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER "

Sealed item rate tender on form 6 & 8 are invited by the Executive Engineer, Mandi Division No-II, H.P.PWD: Mandi for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.PWD so as to reach in his office on or before 25.06.2018 Up to 11.30 A.M. and will be opened on the same day at 3.30 P.M. in the presence of interesting contractors or their authorized representatives who may like to be present. If it happen to be holiday on the tender will be open on next working day. The application for obtaining the tender form will be received up to 3.00 PM on 22.06.2018 and EMD should be attached during the submission of application for obtaining the tender form, without EMD application will not be accepted and the tender form can be had from this office against cash payment (Non refundable) up to 5.00 P.M. on 23.06.2018.

The earnest money in the shape of National Saving Certificate/ Time deposit accounts/Saving account in any of the Post Office and Banks of Himachal Pradesh duly pledged in favour of the Xen must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The earnest should be attached with application. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of The Tender form	Time Limit
	C/O Chhol to Sanehra road in village Chawari km 0/0 to 1/160 (SH:- Tarring work in km 0/715 to 1/160)	Rs.326208/-	Rs.6600/-	Rs.350/-	One month

GENERAL CONDITIONS:-
1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. The contractors whose rates are abnormally low may be asked to furnish the full justification of his rate failing which he will be debarred to compete in tendering for four months.
3.The contractor will not have more than two works in hand at the time of tender and only up to completion of work satisfactory including adherence to quality parameters further work will be awarded to him. All under taking that he is not having more than two works in hand must be recorded in the application.
4.The contractors must have the necessary machinery such as Hot Mix plant, Road Roller etc.

Adv. No.-0837/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDERS.

Sealed item rate tenders are hereby invited on Form 6 & 8 by the Executive Engineer, Solan B & R Division, H.P. PWD. Solan (H.P) on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in H.P.PWD, whose registrations stood renewed as per revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax Act.1968. The important dates of tender are as under: -

Sr. No.	Tender Schedule	
1.	The last date for receipt of application for tender forms.	14.06.2018 Up to 4.00 P.M.
2.	The last date sale of tender forms.	15.06.2018Up to 4.00 P.M.
3.	The last date of Receipt of Tender	18.06.2018Upto 10.30 A.M.
4.	The date of opening of Tender	18.06.2018 11.00 A.M.

The tender shall be received upto 10.30 A.M. on 18.06.2018 and will be opened on the same day at 11.00 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may like to be present. The tender forms can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours. The earnest money in the shape of National Saving Certificate, FDRs in any of the Nationalize Bank duly pledged in favour of the Executive Engineer, (B&R) Division, H.P.PWD, Solan must accompany with each tender, conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Time	Cost of Form
1.	"Special repair to Ayurvedic Health Centre building at Gaura(SH:-Providing civil work i/c repair to water supply & Sanitary installation".	2,42,433/-	5000/-	Two Months.	350/-
2.	"Special repair to Ayurvedic Health Centre building at Gaura(SH:-Providing wooden frames, shutters, painting & plinth protection".	2,30,462/-	4700/-	Two Months.	350/-
3.	"Special repair to Ayurvedic Health Centre building at Gaura(SH:-Providing fencing with barbed wire at the Boundary of dispensary building".	3,23,880/-	6500/-	Two Months.	350/-
4.	"Special repair to Ayurvedic Health Centre building at Gaura(SH:-plastering, painting, white washing, distempering, plinth protection & other minor repair".	3,08,692/-	6200/-	Two Months.	350/-
5.	"Stock storage of HPPWD Solan(SH:- Un- loading of steel Bars, Cement bags & Bitumen drums".	99,945/-	2000/-	Three Months.	350/-

TERMS & CONDITIONS:
1.The tender form will not be issued to those contractors whose performance has been found unsatisfactory.
2.The contactor must have executed similar work successfully during last 3 year
3. Application without earnest money will not be entertained.
4. Contractor should have not more than two works in hand & Contractor should have submit the proof of EPFNo. & GST No. at the time of tender application. Failure should not be issued tender forms.

Adv. No.-0777/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

परिवहन निगम का कमाल–जांच रिपोर्ट में दोषी पाया लेकिन कारवाई की अनुशंसा नही

शिमला/शैल। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार कितनी गंभीर है इसका प्रमाण अभी परिवहन निगम में हुई कंडक्टरों की भर्ती के प्रकरण में भी सामने आया है। कांग्रेस शासन में गया तब मन्त्रीमण्डल ने बाली के समय में ही हुए चयन को सही पाया और इसमें काई भी जांच करवाने से इन्कार कर दिया है।

अब इस भर्ती प्रकरण के बाद

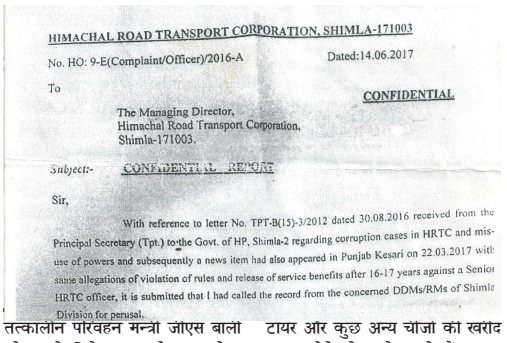

HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION, SHIMLA-171003

No. HO: 9-E(Complaint/Officer)/2016-A Dated:14.06.2017

To

CONFIDENTIAL

The Managing Director,
Himachal Road Transport Corporation,
Shimla-171003.

Subject:- CONFIDENTIAL REPORT

Sir,

With reference to letter No. TPT-B(15)-3/2012 dated 30.08.2016 received from the Principal Secretary (Tpt.) to the Govt. of HP, Shimla-2 regarding corruption cases in HRTC and misuse of powers and subsequently a news item had also appeared in Punjab Kesari on 22.03.2017 with same allegations of violation of rules and release of service benefits after 16-17 years against a Senior HRTC officer, it is submitted that I had called the record from the concerned DDMs/RMs of Shimla Division for perusal.

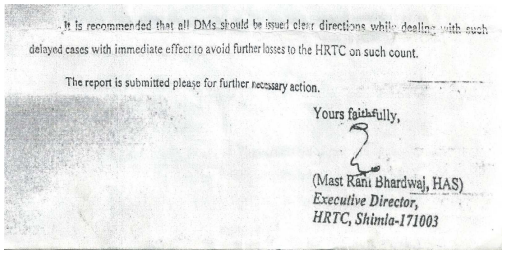

It is recommended that all DMs should be issued clear directions while dealing with such delayed cases with immediate effect to avoid further losses to the HRTC on such count.

The report is submitted please for further necessary action.

Yours faithfully,

(Mast Ram Bhardwaj, HAS)
Executive Director,
HRTC, Shimla-171003

तत्कालीन परिवहन मन्त्री जीएस बाली को इसके लिये भाजपा ने खूब कोसा था। इस पर हर तरह के आरोप लगाये गये थे। भाजपा ने अपने आरोप पत्र में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इसकी जांच करवाने की घोषणा की गयी थी। लेकिन भाजपा का यह आरोप कितना आधारहीन था इसका खुलासा स्वयं जयराम के अपने ही फैसले से हो जाता है। इस कंडक्टर भर्ती प्रकरण की जांच के मुद्दे को जब मंत्रीमण्डल की बैठक में अन्तिम फैसले के लिये रखा टायर और कुछ अन्य चीजों की खरीद घपला होने के आरोप लगे हैं। बजट सत्र में इस आशय का एक प्रश्न भी सदन में आया था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन में इस मामले की जांच करवाये जाने का आश्वासन भी दिया गया था। अब इस आश्वासन के मुताबिक इसकी जांच करवाने की बात की जा रही है लेकिन कुछ जानकारो का मानना है कि जिन अधिकारियों के समय में यह घपले घटे हैं वह आज जयराम सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके प्रभाव के चलते यह सरकार इस जांच को भी आगे नही बढ़ा पायेगी। क्योंकि परिवहन निगम में सारे महत्वपूर्ण फैसले तो एमडी के स्तर पर ही हो जाते हैं इसमें सचिवालय की भूमिका तो बड़ी नगण्य रह जाती है।

भ्रष्टाचार के मामले में परिवहन निगम का तो आलम ही अलग है। निगम में एक समय सारे कायदे कानूनों को नजरअन्दाज करके एक वरिष्ठ अधिकारी डी.एम शिमला अनिल सेन ने कई लोगों को लाखों रूपये का लाभ और निगम को नुकसान पहुंचाया है। जब सेन पर यह आरोप लगे तब परिवहन सचिव ने 30.8.2016 को एमडी को पत्र भेजकर इन आरोपों की जांच के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों पर एमडी ने निगम के ईडी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। ईडी ने इन आरोपों की जांच करने के लिये लायकराम ड्राईवर, गोपाल दास कंडक्टर, मदन लाल और कुन्दन सिंह कंडक्टर की फाईलें तलब की। फाईलों की जांच में ईडी ने पाया कि लायक राम को 16 वर्ष बाद नियमों के विरूद्ध अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करते हुए लाभ दिया गया। इसी तरह गोपाल दास, मदन लाल और कुन्दन सिंह को लाभ दिया गया। इसके लिये डी.एम अनिल सेन अधिकृत नही था।

ईडी ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि "The DM, Shimla Shri Anil Sen was an Appellate Autrhority and not higher to appellate authority and thus exceeded his powers in all above cases. By reviewing such order he has caused financial loss to the HRTC." ईडी मस्त राम भारद्वाज ने 14.6.2017 को एमडी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी लेकिन इस रिपोर्ट में यह प्रस्ताव नही किया कि इस डीएम के खिलाफ कोई कारवाई की जाये। एमडी ने भी रिपोर्ट आने के बाद अपनी ओर से इस पर कारवाई करने के निर्देश नही दिये। जब रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि डी एम अनिल सेन ने अपने अधिकारियों का दुरूप्योग करते हुए निगम को लाखों का नुकसान पहुचाया है तो उसके खिलाफ कारवाई की अनुशंसा क्यों नही की गयी इसका किसी के पास कोई जवाब नही है।

मुकेश का ब्यान सत्ता गंवाने की हताशा:गोविन्द ठाकुर

शिमला/शैल। वन, परिवहन, युवा सेवा एवं खेल मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री के 'जनता त्रस्त, अर्थव्यवस्था चौपट और मोदी विदेश घुमने में मस्त' ब्यान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस नेता का यह ब्यान कांग्रेस सरकार की गत पांच वर्षो के शासनकाल के दौरान कांग्रेस सरकार की विफलताओं व सत्ता गवाने की हताशा को दर्शाता है।

गोविन्द ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता को इस प्रकार के ब्यान देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए तथा जनता को भ्रमित करने के बजाय सच्चाई पेश करनी चाहिए कि पूर्व की यूपीए सरकार ने देश को प्रत्येक क्षेत्रों में विफलताओं की ओर धकेला है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता आज अनाप-शनाप ब्यानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चार वर्षो के कार्यकाल के दौरान देश की युवा शक्ति को अनेकों इनोवेटिव अवसर प्रदान किए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा सात आईआईटी, सात आईआईएम, सात आईआईआईटी तथा कई नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित किए हैं तथा स्किल इण्डिया के माध्यम से एक करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उन्होंने कहा कि जनधन योजना के माध्यम से समाज के निर्धन व वंचित वर्गो तक बैंकिंग लाभ पहुंचाने के साथ-साथ मोदी सरकार ने पिछले चार वर्षो के कार्यकाल में उज्जवला योजना के तहत 3 करोड़ 80 लाख गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं और एक करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास सुविधा प्रदान की गई है।

गोविन्द ठाकुर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने देश को एक वैश्विक ताकत के रूप में उभारा है तथा दुनिया के बड़े-बड़े दशों के मध्य भारत का सम्मान बड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में व्यापत अनिश्चितता का माहौल समाप्त हुआ है और आज दुनिया के बड़े-बड़े औद्योगिक दिग्गज हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षो में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 36.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ-साथ देश के विकास की गति भी बढ़ी है। गत चार वर्षो में एक लाख 69 हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्गो की गति जो कि यूपीए सरकार में 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी अब बढ़कर दोगुना से भी अधिक 27 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है।

गोविन्द ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग अच्छे भविष्य की बुनियाद पर खड़ा है और स्वयं को सुरक्षित हाथों में पा कर दोगुनी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान प्रतिदिन एक नया घोटाला सामने आता था जबकि मोदी सरकार में रोज एक नई जन कल्याणकारी योजना सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

वन मंत्री ने प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को नसिहत देते हुए कहा कि मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान प्रत्येक क्षण राष्ट्र धर्म में व्यतीत करते हैं जबकि कांग्रेस के कई नेता कई-कई दिनों तक बिना कुछ बताए विदेशों में सैर-स्पाटा करते हैं।

योग भारतवर्ष की पुरातन परम्परा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। योग भारतवर्ष की पुरातन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है, जो मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतुष्टि तथा मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का प्रतीक है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने सरकारी निवास ओक-ओवर से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से योगाभ्यास के लिए कुल्लू के ढालपुर मैदान में एकत्र लोगों को सम्बोधित करते हुए कही। जय राम ठाकुर ने कहा योग एक धर्म नहीं है, अपितु जीने की एक कला है जो स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ मन के उद्देश्य को यथार्थ बनाता है। उन्होंने कहा कि योग शरीर को लौकिक ऊर्जा के साथ रिचार्ज करता है तथा पूर्ण सन्तुलन और सद्भाव की प्राप्ति को सहज बनाता है, स्व-उपचार को बढ़ावा देता है, शरीर तथा दिमाग से नकारात्मक बाधाओं को दूर करता है तथा आत्म ज्ञान को बढ़ाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योगाभ्यास की कला शान्तिप्रिय मन तथा शरीर को हासिल करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक विषयों को साथ लाने में मदद करती है। योग लचीलापन और मांसपेशियों की मजबूती बढ़ाने में मदद करता है तथा श्वसन, ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार करता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिसव के रूप में मनाने का सुझाव दिया था और तब से 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'हम फिट तो इण्डिया फिट' अभियान से देश के लाखों लोगों को योग तथा फिटनेस से जुड़े अन्य व्यायामों के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कुल्लू प्रशासन तथा कुल्लू के उपायुक्त यूनुस के प्रयासों की सराहना की।

एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण ने स्वीकृत किए 19 प्रस्ताव

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण (एसएसडब्ल्यूसी एंड एमए) की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

प्राधिकरण ने लगभग 1530 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की संभावना सृजित करने के अतिरिक्त लगभग 588.58 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित निवेश के साथ वर्तमान इकाइयों के विस्तारीकरण तथा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 19 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदर्शित होता है कि राज्य मंद आर्थिक स्थिति के बावजूद निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नए प्रस्तावों में जूस के उत्पादन के लिए ऊना के श्यामपुरा की मैसर्ज बीएस पारस स्पाईसिज कोल्ड चेन प्राईवेट लिमिटेड, मैगनीशा कास्टिंग के उत्पादन के लिए ऊना के गगरेट की मैसर्ज यू. आर. सिंटर प्राईवेट लिमिटेड यूनिट दो, सीए स्टोर तथा ऐप्पलस कंस्ट्रेट के उत्पादन के लिए शिमला के कुमारसैन की मैसर्ज शांतनु इवेस्टमेंटस इंडिया लिमिटेड, एसएस इनगोट के उत्पादन के लिए सिरमौर के नाहन की मैसर्ज मां अब भनभोरी स्टील एंड अलोयज, मैदा, आटा तथा सूजी इत्यादि के उत्पादन के लिए ऊना के अम्ब की मैसर्ज एचएसडी फ्लोर मिल्ज, सिडार ऑयल, असेंसियल ऑयल इत्यादि के उत्पादन के लिए मण्डी के बल्ह की मैसर्ज मणिमहेश इंटरप्राइजिज, लिक्विड इंजेक्टेबलस, आई/ईयर ड्रॉप्स इत्यादि के उत्पादन के लिए सिरमौर के नाहन की मैसर्ज आर.आर. बॉयोटैक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड तथा आटा, मैदा, बेसन एवं सूजी इत्यादि के उत्पादन के लिए उना के ईसपुर की मैसर्ज रूद्र फूडज शामिल हैं।

विस्तृत किए गए प्रस्तावों में टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, पाउडर, तेल, क्रीम, शैम्पू के उत्पादन के लिए सिरमौर के पावंटा साहिब की मैसर्ज तिरूपति मेडिकेयर लिमिटेड, पर्सनल एंड हेयर-केयर उत्पादों के उत्पादन के लिए सोलन के बद्दी मैसर्ज गोदरेज कंजयूमर प्रॉडक्ट लिमिटेड, बेकरी बिस्किटस, फूट वाईन इत्यादि के उत्पादन के लिए सोलन के परवाणू की मैसर्ज राहुल बेकरी, डिटरजेंट पाउडर, टॉयलट साबुन, लिक्वियड शैम्पू इत्यादि के उत्पादन के लिए बद्दी के झाड़माजरी की मैसर्ज आर.एम. कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड यूनिट-दो, डिटोल लिक्वियड, ऐलोपैथिक टैबलेट, ऑइंटमेंट, लिक्वियड तथा आयुर्वेदिक क्रीम ऑइंटमेंटस इत्यादि के उत्पादन के लिए सोलन के बद्दी की मैसर्ज रेकिट बेनकीजर हेल्थ केयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, फास्टनर, एक्सलज, स्टडज, नट्स, पीनियन के उत्पादन के लिए सोलन के नालागढ़ की मैसर्ज माइक्रो टर्नर यूनिट-6, हॉजरी गुड्स के उत्पादन के लिए सोलन के बद्दी की मैसर्ज सौभागिया क्लोदिंग कम्पनी, लिक्वियड इंजेक्शन, पॉवर इंजेक्शन, लिक्वियड ऑयल के उत्पादन के लिए सिरमौर के पावंटा साहिब की मैसर्ज अक म इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, स्टैपलरज, स्टैपलरज रिमूवरज के उत्पादन के लिए सोलन के नालागढ़ की मैसर्ज मयूनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, टॉयलट साबुन, हैंडवॉश के उत्पादन के लिए बद्दी की मैसर्ज गोदरेज प्रॉडक्टस लिमिटेड तथा कॉटन यार्न के उत्पादन के लिए मैसर्ज जीसी फाइबर लिमिटेड को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की।

दण्डनीति के उचित प्रयोग से ही प्रजा की रक्षा संभव है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

महागठबन्धन से चुभन क्यों

कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और जनता दल (एस) ने भाजपा को उसी रणनीतिक शैली में जवाब दिया है जो उसने गोवा, मणिपुर, मेघालय और बिहार में अपनायी थी। कांग्रेस जद(एस) के मुख्यमन्त्री और उप-मुख्यमन्त्री के शपथ समारोह में देश के कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता एक साथ आये हैं। इन नेताओं ने भाजपा को हराने के लिये इकट्ठे होने का संकल्प लिया है। माना भी जा रहा है कि यदि यह गठबन्धन का प्रस्ताव सफल हो जाता है तो भाजपा निश्चित रूप से सत्ता से बाहर हो जायेगी। लेकिन इस गठबनधन की आहट मात्र से ही भाजपा-संघ और उसके पैरोकार परेशान हो उठे हैं। भाजपा-संघ समर्थित मीडिया भी बहुत आहत हो रहा है। सब इस संभावित गठबन्धन को शक्ल लेने से पहले ही इसकी भ्रूण हत्या के प्रयास में जुट गये हैं। जो लोग सक्रिय राजनीति में हैं उनका पहला ध्येय येन-केन-प्रकारेण सत्ता हथियाना होता है और इसके लिये वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा के पक्षधर दल इस दिशा में जो भी कर रहे हैं उसे राजनीति की भाषा में गलत नही कहूंगा। लेकिन आज मीडिया का एक वर्ग और उससे जुड़े लोग जब राजनीतिक दलों की ही भाषा बोलने और लिखने लग जाते हैं तो दुःख होता है।

मैं महागठबन्धन की वकालत नही करूंगा लेकिन इसका विरोध करने वालों से कुछ सवाल जरूर करना चाहूंगा। इसके लिये मैं आपका ध्यान आपातकाल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि कर्नाटक के घटना में जब भाजपा पर यह आरोप आया कि उसने देश में लोकतन्त्र की हत्या कर दी है तब इस आरोप का जवाब कांग्रेस को आपातकाल का स्मरण करके दिया गया। यह सही है कि उस समय लोकतन्त्र को चोट पहुंचाई गयी थी। इस चोट का प्रतिकार करने के लिये उस समय का विपक्ष इकट्ठा हुआ था और जनता पार्टी गठित हुई थी। 1980 में यह जनता पार्टी जनसंघ घटक की दोहरी सदस्यता के कारण क्यों टूटी और शिमला के रिज मैदान पर तत्कालीन केन्द्रिय मन्त्री राजनारायण की गिरफ्तारी क्यों हुई तथा उसका जनता पार्टी के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा था मैं इसकी व्याख्या में नही जाना चाहता। लेकिन यह सवाल जरूर उठाना चाहता हूं कि क्या आज भी आपातकाल जैसे हालात नही बनते जा रहे हैं? क्या आडवाणी जी ने भी इसका संकेत नही दिया है? आज क्या एनडीए में भाजपा के साथ अन्य दल नही है? क्या पीडीपी और नीतिश के जद (यू) के साथ चुनाव परिणामों के बाद गठबन्धन नही बने हैं।

इसलिये आज यदि इस संभावित आपातकाल का सामना करने के लिये एक महागठबन्धन आकार ले रहा है तो इसमें बुराई क्या है। क्या आज यह स्मरण नही किया जाना चाहिये कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश की जनता के साथ जो अच्छे दिनों के वायदे किये गये थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं। उस समय मोदी जी ने यह कहा था कि वह प्रधानमंत्री नही वरन् प्रधान चौकीदार बनकर देश की सेवा करेंगे। लेकिन क्या इस चौकीदार के सामने से ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग देश का हजारों करोड़ लेकर फरार नही हुए हैं। जिस कालेधन और भ्रष्टाचार को ढ़ोल पीटकर सत्ता में आये थे क्या उस दिशा में एक भी ठोस कदम उठाया गया है। आज सरकारी बैंको का एनपीए सात लाख करोड़ से भी ऊपर जा पहुंचा हैं। क्या यह जनता के पैसे की दिन दिहाड़े डकैती नही हैं। क्या इस एनपीए को वसूलने के लिये कोई कदम उठाया गया है। बल्कि जिन नौजवान बैंक मैनजरों ने एनपीए को लेकर सख्ती दिखायी उन्हे नीतिश के बिहार में गोली मार दी गयी। क्या एनपीए के नाम पर शीर्ष बैंक प्रबन्धन अपनी बईमानी को छिपा सकता है। क्या यह सही नही है कि इसी एनपीए के कारण बैंको मे पैसे की कमी का प्रभाव सरकार के राजस्व पर भी पड़ा है। क्योंकि इसी एनपीए वालों को अपरोक्ष में लाभ देने के लिये ही तो नोटबंदी लायी गयी थी। यदि कालेधन को लेकर सरकार का आकलन और सूचना सही होती तो स्थिति ही कुछ और होती। पुराने नोट बन्द करने के बाद जब वही नोट पूरी करंसी का करीब 90% वापिस आ गया और उसे बदलना पड़ा तो सारा गणित गड़बड़ा गया। इसी कारण से आज सरकार तेल की कीमतें बढाकर अपना राजस्व इकट्ठा कर रही है। तेल को इसी कारण से जीएसटी के तहत नहीं लाया जा रहा है। इस तरह के आज अनेकों कारण ऐसे खड़े हो गये हैं जो आपातकाल से भी बदत्तर स्थिति बन गयी है। विरोध की हर आवाज़ को देशद्रोह कहने का चलन शुरू हो गया है।

इस परिदृश्य में आज देश को मन्दिर-मस्जिद, हिन्दु-मुस्लिम और दलित बनाम अन्य के नाम पर ज्यादा देर तक नही चलाया जा सकता। किसान आत्महत्या के कगार पर पहुंचा हुआ है। लाखों टन अनाज खुले में बर्बाद हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। क्या यह सारे कारण एक नये राजनीतिक गठबन्धन की आवश्यकता नही बन जाते? इस संभावित गठबन्धन को नेता के प्रश्न पर जिस तरह तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें मीडिया का भी एक वर्ग सक्रिय भूमिका निभाने में लग गया है वह चिन्ता और निंदा का विषय है।

हिमाचल प्रगतिशील कृषि राज्य बनने की ओर अग्रसर

राज्य सरकार अगले पांच वर्षो के दौरान हिमाचल प्रदेश को जैविक कृषि राज्य में बदलने की परिकल्पना करती है। वर्तमान में 21,473 हेक्टेयर क्षेत्र में 39,790 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश में स्वस्थ एवं रासायनिक तत्व रहित अनाज के उत्पादन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए जैविक तथा शून्य लागत प्राकृतिक खेती प्रणाली को बढ़ावा दे रही है।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत की प्रेरणा तथा कृषि विशेषज्ञ पदमश्री सुभाष पालेकर के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 'प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह योजना कम लागत की जलवायुपरक शून्य बजट प्राकृतिक खेती प्रणाली को अपनाकर प्रकृति के अनुरूप कृषि आय बढ़ाने की परिकल्पना पर आधारित है। इस प्रणाली से न केवल मिट्टी की उर्वरकता, पानी के रिसाव व संरधता में सुधार होगा बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के अलावा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी हतोत्साहित करेगा।

राज्य स्तर पर शून्य लागत प्राकृतिक खेती के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मंत्री तथा कृषि व संबद्ध विभागों के विभागाध्यक्ष समिति के सदस्य होंगे, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि इसके सदस्य सचिव होंगे।

कृषि निदेशालय में एक राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई का गठन किया जाएगा। इसी तरह जिला और खण्ड स्तरों पर भी इकाईयों का गठन किया जाएगा। राज्य में जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्य बल पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। यह शून्य लागत प्राकृतिक खेती के कार्यान्वयन से जुड़े सभी प्रस्तावों पर विचार करेगा तथा उन्हें मंजूरी देगा।

शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करने के लिए क्षमता निर्माण और जन जागरूकता, इस योजना के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक अथवा जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी संगठनों, कृषक समितियों तथा एजेन्सियों को भी योजना के प्रसार और प्रमाणन गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।

प्रगतिशील किसानों का चयन प्रति क्लस्टर किया जाएगा और इन्हें शून्य लागत प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसान, क्लस्टर स्तर पर स्त्रोत व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) हो सकते हैं। प्रस्तावित क्लस्टरों में ऐसे किसान शामिल हो सकते हैं जो जैविक कृषि का कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे किसानों की 100 प्रतिशत कवरेज के लिए

प्रस्तावित क्लस्टर के दायरे में आते हों। प्रशिक्षित प्रगतिशील किसान शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए अन्य किसानों को प्रेरित करेंगे तथा उन्हें समर्थन प्रदान करेंगे। इस सम्बन्ध में जिला टीमों द्वारा भी किसानों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया जाएगा। आरम्भ में किसानों को छोटी इकाई में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा चरणबद्ध ढंग से वे अपने पूरे क्षेत्र को इसके तहत ला सकते हैं। किसानों को शिक्षित करने के लिए विभाग तथा जिला इकाईयों द्वारा खण्ड स्तर तक जन जागरूकता कार्यक्रमों तथा किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। स्त्रोत व्यक्ति एवं विशेषज्ञ मानदेय के लिए पात्र होंगे।

चौधरी श्रवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय और डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के परीक्षणों के उपरान्त विभिन्न फसलों को व्यवहार्य बनाने के लिए पैकेज विकसित करेंगे। दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा स्थान विशेष शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के मिले जुले म डल विकसित किए जाएंगे।

शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पूरी तरह से देसी गाय की नस्लों पर आधारित है। पशुपालन विभाग द्वारा उच्च किस्म की घरेलू गाय जर्मप्लाज्म की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शून्य लागत प्राकृतिक खेती इनपुट हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। कृषि इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में एक दुकान की सुविधा प्रदान की जाएगी। शून्य लागत प्राकृतिक खेती कर रहे किसान जिनके पास भारतीय नस्ल की गाय हैं, वे दुकान के मालिक होंगे तथा इस खेती को अपनाने वाले किसानों को कम दरों पर कृषि इनपुट की बिक्री करेंगे। दुकान मालिक को बाह्य इनपुट, उपकरणों, पैकेजिंग, ड्रम, कन्टेनर व किराया इत्यादि के लिए तीन वर्षो के लिए 50 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।

शून्य लागत प्राकृतिक खेती के लिए अनिवार्य इनपुट गाय का गोबर तथा मूत्र के कुशल संग्रह की सुविधा के लिए किसानों को पशुशालाओं तथा मूत्र संग्रहण प्रणाली के निर्माण के लिए 80 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। कीट प्रबन्धन के लिए 75 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। शून्य लागत कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधा के लिए भागीदारी गारंटी प्रणाली/तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा। भारत सरकार की दिशा-निर्देशानुसार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना से न केवल राज्य में प्रगतिशील खेती को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आने वाले वर्षो में सभी किसानों को चरणबद्ध तरीके से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे भविष्य में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

मोदी सरकार के चार सालः देश का हाल बेहाल

–उपेन्द्र प्रसाद–

इन चार सालों के दौरान देश में सामाजिक सौहार्द में भारी गिरावट आई है। देश की आबादी का 14 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। 16 फीसदी आबादी वाला दलित समुदाय भी अपने आपको असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री भीमधुन का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। लेकिन उनका भीमधून दलितों के किसी काम का नहीं है। दलितों पर आक्रामण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनको मिलने वाले आरक्षण को भी तरह तरह के नये नियमों के द्वारा कमजोर किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी विभागों में लाखों सीटें खाली हैं, लेकिन उनको भरने के भर्ती अभियान चलाया नहीं जा रहा है। ठेके को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन ठेकों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं।

नरेन्द्र मोदी सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं और उसे अपने आपको साबित करने के लिए सिर्फ एक साल ही बचा है। इन चार सालों की उपलब्धियों को यदि हम खुद मोदीजी के चश्मे से देखें, तो पाएंगे कि उन्होंने बैंकों में उन करोड़ों लोगों के खाते खुलवा दिए, जो बैंकों का हिस्सा होने की सोच भी नहीं सकते थे। उनका एक दावा देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण करवा देना है। वैसे यह योजना पहले से ही चल रही थी और मोदी जी के कार्यकाल में 18 हजार गांवों को बिजली से जोड़ा गया, जबकि देश में 2 लाख से भी ज्यादा गांव है। यानी उनके कार्यकाल के पहले ही 91 प्रतिशत गांव बिजली से जुड़ चुके थे, शेष 18 फीसदी गांवों को उनके कार्यकाल में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त उनका एक दावा करोड़ों गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भी चर्चा करते हैं, जिसके तहत करोड़ों को कर्ज दिए गए, ताकि वे अपने अपने रोजगारों को बढ़ा सकें।

इन दावों की क्या हकीकत है, इसकी सोशल ऑडिट से ही इसका पता चलेगा। यदि इन दावों को आंशिक रूप से मान भी लिया जाये, तो यह कहने में कोई गलतबयानी नहीं होगी कि जिन कारणों से मोदीजी को सत्ता मिली थी, उनमें सबसे प्रमुख कारण लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश था। लोगों को लग रहा था कि मोदीजी खुद परिवार वाले व्यक्ति नहीं हैं और इसलिए वे भ्रष्ट नहीं हो सकते और उनको भ्रष्ट भी नहीं बनाया जा सकता है। 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' का उनका वायदा लोगों को भा गया था। ' बहुत हुआ अब भ्रष्टाचार, अबकी बार मोदी सरकार' के नारे पर लोग मुग्ध थे। लेकिन सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार न केवल जारी है, बल्कि यह बढ़ भी गया है। मोदी जी द्वारा बार बार यह कहने से कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लोग भ्रष्टाचार की मार से नहीं बच पा रहे। अभी हाल ही में दिल्ली के एक थाने में भाजपा के ही एक पूर्व विधायक के बेटे और पोते की पुलिस ने इसलिए पिटाई कर दी, क्योंकि बिना घूस दिए ही वह अपनी जब्त स्कूटर वहां से ले जाना चाहता है।

सच तो यह है कि भ्रष्टाचार पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का भय जब तक रहा, यहां विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार वास्तव में बहुत कम हो गए थे। लेकिन मोदी जी की सरकार ने केजरीवाल सरकार की शक्तियां छीन उसे पंगु बना दिया और फिर पहले ही तरह भ्रष्टाचार अपने चरम पर। एक तरह से मोदीजी केजरीवाल को यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि 'न भ्रष्टाचार रोकूंगा, और न ही तुम्हें भ्रष्टाचार रोकने दूंगा'।

मोदीजी का एक और नारा था, 'बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार'। लेकिन यह नारा भी पिछले चार सालों में गलत साबित हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई वहां ज्यादा बढ़ी है, जहां सरकार का हस्तक्षेप है या जहां सरकार द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। मेट्रो का किराया इतना बढ़ा दिया गया कि उससे चलने वाले लोगों की संख्या ही घट गई और किराया बढ़ाकर घाटा कम करने का इरादा भी शायद पूरा नहीं हो। रेल किराये में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और पूरा रेल महकमा धीमा पड़ा हुआ है। इस समय ट्रेनें जितना लेट चल रही हैं, उतना शायद ही पिछले 25 साल के इतिहास में कभी लेट चली हो।

मोदीजी का एक नारा था कि हम सरकार को छोटा करेंगे और प्रशासन को अधिकतम बना देंगे। सरकार छोटी हुई हो, ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन सरकार के मंत्रालयों के काम अवश्य धीमें पड़ गए हैं। भारतीय बाबूशाही कभी भी तेज नहीं रही, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इसकी सुस्ती और भी बढ़ गई है। अनिर्णय का माहौल और भी बढ़ गया है, भले ही राजनैतिक प्रशासन के स्तर पर मोदीजी तेज निर्णय लेने का दावा करते रहे हैं।

इन चार सालों के दौरान देश में सामाजिक सौहार्द में भारी गिरावट आई है। देश की आबादी का 14 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। 16 फीसदी आबादी वाला दलित समुदाय भी अपने आपको असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री भीमधुन का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। लेकिन उनका भीमधून दलितों के किसी काम का नहीं है। दलितों पर आक्रामण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनको मिलने वाले आरक्षण को भी तरह तरह के नये नियमों के द्वारा कमजोर किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी विभागों में लाखों सीटें खाली हैं, लेकिन उनको भरने के भर्ती अभियान चलाया नहीं जा रहा है। ठेके को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन ठेकों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। इससे भी बदतर हालत यह है कि ठेके में भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही एसएससी से होने वाली नियुक्तियों में भारी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे।

इन भ्रष्टाचारों के कारण युवकों में भारी रोष है। मोदी जी ने स्किल्ड इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अंग्रेजी जुमलों वाले अनेक स्कीम चला रखे हैं। लेकिन उनसे देश के रोजगार पटल पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अमेरिकी नीतियों के कारण आईटी सेक्टर कमजोर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में यह और भी कमजोर हो सकता है। देश के हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं और हजारों ने बंद होने के आवेदन दे रखे हैं। अब उन्हें छात्र नहीं मिलते, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी उनको काम नहीं मिलता। जले पर नमक छिड़कते हुए मोदी के लोग उन्होंने पकौड़ों की दुकान खोलने की सलाह दे डालते हैं, लेकिन यह नहीं बताते ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर वे पकौड़े की दुकान खोलेंगे, तो फिर उनका क्या होगा, जो पहले से ही पकौड़ा बेच रहे हैं। मोदी की सरकार के गठन के चार साल बाद आज अर्थतंत्र ध्वस्त सा दिखाई दे रहा है। वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है। बैंकों की हालत नाजुक हो गई है। उनकी विश्वसनीयता भी गिरती जा रही है और जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं, वे भयभीत हैं और उनमें से अनेक अब नोट अपने पास रख रहे हैं, जिसके कारण बैंको में भी नोटों की किल्लत और उसके कारण खाली एटीएम की तस्वीरें आने लगती हैं। कुल मिलाकर आज देश की स्थिति ठीक नहीं है।

(देशबन्धु से साभार)

देश बदलना है तो देना होगा युवाओं को सम्मान

''डॉ. नीलम महेंद्र''

भारत एक युवा देश है। इतना ही नहीं , बल्कि युवाओं के मामले में हम विश्व में सबसे समृद्ध देश हैं। यानि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा युवा हमारे देश में हैं। भारत सरकार की यूथ इन इंडिया, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 1971 से 2011 के बीच युवाओं की आबादी में 34.8: की वृद्धि हुई है। बता दिया जाए कि इस रिपोर्ट में 15 से 33 वर्ष तक के लोगों को युवा माना गया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2030 तक एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन में युवाओं की संख्या जहां कुल आबादी की 22.31% होगी, और जापान में यह 20.10% होगी, भारत में यह आंकड़ा सबसे अधिक 32.26% होगा। यानी भारत अपने भविष्य के उस सुनहरे दौर के करीब है जहाँ उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊँचाईयों को छू सकती है।

लेकिन जब हम युवाओं के सहारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात करते हैं तो इस बात को समझना आवश्यक है कि, युवा होना केवल जिंदगी में जवानी का एक दौर नहीं होता जिसे आंकड़ों में शामिल करके गर्व किया जाए। यह महज उम्र की बात नहीं होती। यह विषय उस से कहीं अधिक होता है।

यह विषय होता है असीमित सम्भावनाओं का।

यह विषय होता है सृजनात्मकता का।

यह विषय होता है कल्पनाओं की उड़ान का।

यह विषय होता है उत्सुकता का।

यह विषय होता है उतावलेपन के दौर का।

यह समय होता है ऊर्जा से भरपूर होने का।

यह समय होता है सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने का।

यह दौर होता है हिम्मत का।

कहा जा सकता है कि युवा या यूथ चिड़िया के उस नन्हे से बच्चे के समान है जो अभी अभी अपने अण्डे को तोड़कर बाहर निकला है और अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाकर उम्मीद और आजादी के खुले आकाश में उड़ने को बेकरार है।

यह बात सही है कि किसी भी देश के युवाओं की तरह हमारे देश के युवाओं में भी वो शक्ति है कि वो भारत को एक विकासशील देश से बदलकर एक विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दें।

इस देश से आतंकवाद और दहेज जैसी समस्याओं को जड़ से मिटा दे।

लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा देश को बदल सकते हैं तो क्या हम यह भी सोचते हैं कि वो कौन सा युवा है जो देश बदलेगा?

वो युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है?

वो युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है?

वो युवा जो वंशवाद का मुखौटा ओढ़कर स्वयं को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है?

वो युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी कर देश छोड़कर चले जाने के लिए विवश हैं?

वो युवा जिसके हाथों में डिग्रियाँ तो हैं लेकिन विषय से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है?

वे साक्षर तो हैं शिक्षित नहीं?

शिक्षित तो छोड़िए संस्कारित भी नहीं?

या वो युवा जो कभी तीन माह की तो कभी तीन साल की बच्ची तो कभी निर्भया के बलात्कार में लिप्त है?

वो युवा जो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स की गिरफ्त में है?

या फिर वो युवा जो कालेज कैम्पस में किसी राजनैतिक दल के हाथों का मोहरा भर है?

तो फिर कौन सा युवा देश बदलेगा?

इसका जवाब यह है कि परिस्थितियां बदलने का इंतजार करने के बजाए हम स्वयं पहल करें।

अगर हम चाहते हैं कि युवा इस देश को बदले तो पहले हमें खुद को बदलना होगा।

हम युवाओं का भविष्य तो नहीं बना सकते लेकिन भविष्य के लिए युवाओं को तैयार तो कर ही सकते हैं।

हमें उन्हें सही मायनों में शिक्षित करना होगा।

उनका ज्ञान जो किताबों के अक्षरों तक सीमित है उसे व्यवहारिक ज्ञान की सीमाओं तक लाना होगा।

उसे वो शिक्षित युवा बनाना होगा जो नौकरी देने वाला उद्यमी बने, एक एन्टरप्रेन्योर बने न कि नौकरी ढूंढने वाला एक बेरोजगार।

उन्हें शिक्षित ही नहीं संस्कारित भी करना होगा।

उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना होगा।

पैसों से ज्यादा उन पर समय खर्च करना होगा।

उन्हें प्रेम तो हम देते हैं सम्मान भी देना होगा।

हमें उन युवाओं का निर्माण करना होगा जो देश के सहारे खुद आगे जाने के बजाय अपने सहारे देश को आगे ले जाने में यकीन करते हों।

हमें सम्मान करना होगा उस युवा का जो सड़क किनारे किसी बहते हुए नल को देखकर चुपचाप निकल जाने के बजाये उसे बन्द करने की पहल करता है।

हमें आदर करना होगा उस युवा का जो कचरा फेंकने के लिए कूड़ादान ढूँढता है लेकिन सड़क पर हर कहीं नहीं फेंक देता।

हमें अभिवादन करना होगा उस युवा का जो भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने के बजाय लड़ना पसंद करता है।

हमें आदर करना होगा उस युवा का जो दहेज लेने से इंकार कर देता है।

हमें इज्जत देनी होगी उस युवा को जो महिलाओं का सम्मान करना जानता हो उनका बलात्कार नहीं।

हमें सत्कार करना होगा उस युवा का जो फूलों का बगीचा लगाने में विश्वास करता है फूल तोड़ने में नहीं।

और यह हर्ष का विषय है कि ऐसे युवा हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास हमारे बीच आज भी हैं, बहुत हैं। आज जब हमारा सामना ऐसे किसी युवा से होता है तो हम मन ही मन में उसकी प्रशंसा करते हैं और निकल जाते हैं। अब जरूरत है उन्हें ढूंढने की और सम्मानित करने की। आवश्यकता है ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने की। एक समाज के रूप में, एक संस्था के रूप में।

ऐसे युवाओं को जब देश में सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, इन्हें शेष युवाओं के सामने यूथ आइकान और रोल मोडल बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, तो न सिर्फ यह इसी राह पर डटे रहने के लिए उत्साहित होंगे बल्कि देश के शेष युवाओं को उनकी सोच को एक लक्ष्य मिलेगा एक दिशा मिलेगी। जब हमारे देश के युवा सही दिशा और सही लक्ष्य पर चल निकलेंगे तो सही मायनों में यह कहा जा सकता है कि आने वाला कल भारत का ही होगा।

मुख्यमंत्री ने आरम्भ की तीन महत्वकांक्षी योजनाए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के विकास एवं कल्याण के लिए महत्वकांक्षी योजनाओं का शुभारम्भ किया। 'जनमंच' योजना से लोगों की समस्याओं का प्रभावी ढंग से निपटारा तथा 'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना' का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता उपलब्ध करवाना है और 'हिमाचल गृहणी सुविधा योजना' के तहत भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई 'उज्जवला योजना' के अन्तर्गत लाभान्वित न हो सकी महिलाओं को रसोई गैस सिलेण्डर की प्रतिभूति तथा गैस चुल्हा उपलब्ध करवा कर उनका सुदृढ़ीकरण एवं पर्यावरण सरक्षण सुनिश्चित बनाना है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि यह सभी योजनाएं आज केन्द्र सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आरम्भ की गई इन सभी योजनाओं से प्रदेश के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने अन्य राष्ट्रों के बीच देश का विशेष स्थान सुनिश्चित बनाया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पूर्ण सहयोग दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमंच योजना से लोक शिकायतों के निवारण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से न केवल लोगों के लिए आरम्भ की गई कल्याणकारी योजनाएं समय पर सुनिश्चित होगी बल्कि इससे वांछित परिणाम प्राप्त होने भी सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि जनमंच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार आयोजित किए जाएंगे और यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि इनका गठन निर्वाचन क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्रों में किया जाए ताकि

दूरदराज क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों का निवारण उनके घर के नजदीक सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 'जनमंच' प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों व सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रत्येक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित बनानी होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को मशीनरी खरीदने के लिए 25 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा और 40 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए यह उपदान राशि 30 प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज उपुदान भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहणी सुविधा योजना का उद्देश्य महिलाओं का सुदृढ़ीकरण व पर्यावरण संरक्षण है। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि उज्जवला योजना के अन्तर्गत लाभान्वित न होने वाले सभी परिवारों को गैस कनेक्शन सुनिश्चित बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत रसोई गैस सिलेण्डर व गैस चुल्हा खरीदने के लिए 3500 रुपये का पैकेज प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां प्रत्येक घर की रसोई धुआं रहित होगी।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचार सुनिश्चित बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न भागों के लोगों से उनकी समस्याओं के निपटान बारे वार्तालाप किया। उन्होंने इस अवसर पर जनमंच योजना की दिशा-निर्देशिका जारी की। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना की दिशा-निर्देशिका का भी विमोचन किया। उन्होंने लाभार्थियों को हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन के दस्तावेज भी प्रदान किए।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार न केवल अपने वायदों को पूरा कर रही है बल्कि प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाएं आरम्भ कर उससे उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर लोगों को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए 30 नई योजनाएं आरम्भ करने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल गृहणी सुविधा योजना एक नवीन योजना है, इससे राज्य की महिलाओं का सुदृढ़ीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 33,600 महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग ने प्रदेश के लोगों को लाभान्वित करने के लिए एक ऐप भी आरम्भ किया है।

मोदी सरकार के चार वर्ष के सफल कार्यकाल पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके चार वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी है तथा कहा कि इन चार वर्षों में देशभर में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है तथा भारत का विश्व मंच पर मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के लोगों से विशेष लगाव तथा विभिन्न योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक धनराशि आबंटित करने व विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आर्शीवाद से प्रदेश में केन्द्र सरकार की सहायता से अनेक विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा गत चार वर्षों के दौरान नरेन्द्र मोदी के कुटनीतिक प्रयासों से अन्य राष्ट्रो के साथ सम्बन्धों में सुधार आया है। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय मंच पर भारत को मित्रतापूर्ण छवि के साथ उभारा है। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत को अन्य राष्ट्रों से सम्मान प्राप्त हुआ है और विदेशी निवेशक देश में निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा, जो प्रधानमंत्री के चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनकी दूरदृष्टि से आरम्भ की गई महत्वकांक्षी योजनाओं व कार्यक्रमों से अछुता रहा हो। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, मेक-इन-इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान, उज्जवला योजना, कौशल विकास मिशन, डिजिटल इण्डिया और अन्य योजनाओं से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ है। लोगों से 'मन की बात' के माध्यम से संवाद स्थापित करने से सरकार व लोगों की बीच की दूरी कम हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी प्रत्येक राजनेता व देश के नागरिकों के प्रेरणा स्त्रोत बन कर उभरे हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए घण्टों तक कार्यालय में कार्य करने में समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने मोदी के भविष्य में और सफलता की कामना की है।

मोदी सरकार के 4 साल,भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन युक्तःअनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र में मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इस सरकार को सभी वर्गों के हितों में कार्य करने वाली सरकार बताते देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने वाली सरकार बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा 'आज से ठीक चार साल पहले देश ने पूरवर्ती भ्रष्टाचारी कांग्रेस शासन से मुक्ति पा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विकासवादी सरकार को शपथ लेते देखा था। तब से लेकर आज तक साल दर साल मोदी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास, पिछड़े इलाकों में मूलभूत सुविधाएँ, सभी वर्गों के उत्थान और विदेशों में भारत की गरिमामयी छवि गढ़ने का कार्य कर रही है।आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छू रहा है और इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री समेत पूरे कैबिनेट को चार सफल वर्षों के लिए बधाई देता हूं, मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरेगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा पिछले 4 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। मोदी सरकार के इन चार सालों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। आर्थिक, सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर देश सशक्त हुआ है, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये सरकार साफ नीयत और सही विकास के मापदंडो पर चलते हुए देश को एक प्रगतिशील नेतृत्व देने में सफल हुई है।

ठाकुर ने कहा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 एक नए भारत का सपना देखा है जहां गरीबों और पिछड़ों के लिए समानता के बराबर अवसर होंगे, एक नया भारत जहां गरीबों को दान के जरिए कुछ नहीं चाहिए होगा बल्कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा उपलब्ध करायंगे कि वो अपने बलबूते पर सब हासिल करेंगे, युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर मुहैया कराए जाएँगे जो 'न्यू इंडिया' के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र की मोदी सरकार देश की उन्नति किए प्रतिबद्ध है तभी तो बात चाहे बेटियों के लिए शुरू की गई प्रधान मंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की हो या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सौभाग्य योजना से 4 करोड़ परिवार को बिजली, 90 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब का वितरण, मिशन इंद्रधनुष,स्किल इंडिया प्रोग्राम से 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग ,स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 3.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन,जनधन योजना से 31 करोड़ बैंक खाते, स्वच्छ भारत अभियान, मुद्रा योजना से 12 करोड़ उधमीयों को 6 लाख करोड़ का लोन, वन रैंक वन पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग का कल्याण कर रही है।

हिमाचल में निपाह वायरस का कोई मामला नही

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक निपाह वायरस बीमारी का राज्य में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चमगादड़ों की मौत तथा मनुष्यों में निपाह वायरस के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आशंकित निपाह वायरस मामलों की सक्रिय निगरानी तथा इसकी नित्य प्रति रिपोर्टिंग के लिए एडवाईजरी भी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना है और इस संबंध में किसी भी आशंका अथवा सुझाव के लिए टॉल फ्री नम्बर 104 पर सम्पर्क करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के धगेड़ा खण्ड के बर्मापापड़ी गांव में कुछ चमगादड़ों की मौत की सूचना है। सिरमौर के उपायुक्त के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों के एक दल ने उसी दिन स्थल का दौरा किया तथा एनआईवी पुणे और जालंधर में परीक्षण के लिए नमूने एकत्रित किए। उन्होंने कहा कि ऊना जिले से भी कुछ चमगादड़ों की मौत का मामला सामने आया है। इस मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

'बेटी है अनमोल योजना' के अंतर्गत राशि में बढ़ौतरी

शिमला/शैल। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 'बेटी है अनमोल योजना' के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों पर प्रत्येक के नाम जमा करवाई जाने वाली मौजूदा 10 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया है। यह बढ़ी हुई राशि 19 मई, 2018 को जारी अधिसूचना की तिथि से देय होगी।

नगर निगम टैंकरों से उपलब्ध कराये पानी मुख्यमंत्री के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने शिमला में जलापूर्ति को सुचारू कर लोगों को शीघ्र राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी पानी की कमी का सामना न करना पड़े तथा सभी क्षेत्रों में एक समान जलापूर्ति उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने पानी के रिसाव को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने नगर निगम शिमला के आयुक्त रोहित जम्वाल को निर्देश दिए कि पानी के टैकरों के माध्यम से विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की काफी कमी है, में प्राथमिकता के आधार पर पानी उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि पानी के टैकरों की कमी सामने आती है तो अतिरिक्त पानी के टैकरों की व्यवस्था भी की जाए।

पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में स्थानीय उद्यमियता को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना – 2018' की प्रारूप अधिसूचना को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में महिला सशक्तिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए 'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना' आरम्भ करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही 'उज्ज्वला' योजना से छूटे घरों को एलपीजी गैस कनैक्शनों तथा गैस चूल्हों के लिए प्रतिभूति राशि प्रदान करेगी।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद् अध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 11000 रुपये तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष को 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये, जिला परिषद सदस्य का 3500 से बढ़ाकर 4500 रुपये, पंचायत समिति अध्यक्ष का 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपये, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष का 3500 से बढ़ाकर 4500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य का 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये, ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये तथा उप-प्रधान ग्राम पंचायत का 2200 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत सदस्य का बैठक भत्ता माह में अधिकतम दो बैठकों के लिए बढ़ाकर मौजूदा 225 रुपये से 240 रुपये प्रति बैठक किया गया है।

मंत्रिमण्डल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का राज्य हिस्सा बढ़ाकर क्रमशः 1450 से 1750 रुपये, 600 से 900 रुपये तथा 750 से 1050 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस बढ़ौतरी से अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 4750 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2400 रुपये तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3300 रुपये का मानदेय मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने 'डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना' के अंतर्गत वार्षिक छात्रवृत्ति को 10000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये तथा इस छात्रवृत्ति के लिए 10 जमा एक जमा दो कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने वित्त विभाग द्वारा 11 नवम्बर, 2014 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए सभी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों जो स्वैच्छिक/समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक हैं, को 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन प्रदान करने के लिए प्रोसपेक्टिव स्थिति में छूट देने की मंजूरी प्रदान की।

पूर्व में राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत प्रावधान किया था कि निजी हित में स्वैच्छिक/समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो, लेकिन 33 वर्ष से कम का हो, वे 33 वर्ष के समानुपातिक आधार पर पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, अर्थात् ऐसे सरकारी कर्मचारी केवल 33 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए हि.प्र. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 333 पदों का भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बिजली शिकायत विशेषकर नए कनैक्शन लगाने की प्रणाली को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया। वितरण नुकसान की शून्य प्रणाली पर भी बल दिया गया। मण्डल स्तर पर त्वरित कारवाई दल बनाने पर बल दिया गया ताकि आपातकालीन स्थिति में शीघ्र कारवाई की जा सके।

बैठक में बल दिया गया कि पूरी होने के समीप की सभी परियोजनाओं को शीघ्र चालू किया जाए तथा अन्य परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए। मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में सौर कुकरों की व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मंत्रिमण्डल ने इस पर बल दिया कि विभाग को लक्ष्यों पर कार्य करना चाहिए ताकि औद्योगिक इकाईयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती/बाधित न हो।

बैठक में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने तथा सूची प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि बिजली की कमी न हो।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला झुड्डोवाल को राजकीय उच्च विद्यालय, मण्डी जिले की राजकीय माध्यमिक पाठशाला पिपलागलु, नौण, जंझर तथा बुरहाटा को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मण्डी जिले की राजकीय उच्च पाठशाला तरौर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ऊना जिले की राजकीय उच्च पाठशाला चुरड़ी तथा सासन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 38 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत थारू में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुहार, मरोतां, गहगोरी, गुरू का लाहौर, मल्यावर तथा ऋषिकेश तथा हमीरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चकमोह के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक में एक पद फार्मासिस्ट तथा एक-एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सृजित करने तथा भरने के लिए मंजूरी प्रदान की।

बैठक में कमला नेहरू मातृ एवं शिशु राज्य अस्पताल शिमला में स्टाफ नर्सों के 15 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में दैनिक भोगी आधार चालकों के 10 पद भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में अनुबंध आधार पर कल्याण संजोजकों के 7 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के माप व तोल संगठन में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से मेनुअल एसिस्टेंट के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विशेष रूप से सक्षमों के सशक्तिकरण विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 7 पद भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 4 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री के गृह निर्वाचन सभा क्षेत्र थुनाग में पंचायती राज विभाग के कैम्प कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने वर्तमान में कुल्लू जिले की पुलिस पोस्ट न्यूली (सैंज) के अधीन ग्राम पंचायत गड़ापारली, शंघाड़, देहुड़ीधार, शेशर को पुलिस स्टेशन भुंतर के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के पुलिस स्टेशन नुरपूर की ग्राम पंचायत हरनोटा, दसोली, भोल तथा वनोली को पुलिस स्टेशन ज्वाली में स्थानान्तरित करने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य सरकार ने कसौली घटना में पांच अधिकारियों को किया निलम्बित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने मण्डलायुक्त शिमला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की संस्तुति पर कसौली गोलीकांड घटना में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोताही बरतने, अव्यवसायिक तथा असंबद्ध रवैया अपनाने पर 14 अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई अमल में लाई है।

सरकार ने सोलन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, परवाणु के तत्कालीन एसडीपीओ रमेश शर्मा, कसौली के नायब तहसीलदार जगपाल सिंह, धर्मपुर के एसएचओ मदन सिंह तथा कसौली के एसएचओ दलीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

मोहित चावला (भापुसे) के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

सरकार सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के अंतर्गत नौ और कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ कर रही है और तदानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इनमें एचसी नागेन्द्र पीपी सायरी, एचएचसी हेमराज पीएस दाड़लाघाट, कांस्टेबल संजीव पीएस धर्मपुर, कांस्टेबल सुनील पीएस धर्मपुर, एलसी चम्पा, एलसी उषा तथा एलसी शारदा पीएस धर्मपुर, कांस्टेबल ईश्वर तथा कांस्टेबल नरेन्द्र पीएल सोलन शामिल हैं।

आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिये हर संभव प्रयास करें अधिकारी : वनमंत्री

शिमला/शैल। वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि तापमान में अचानक वृद्धि होने व वातावरण में नमी की कमी के कारण जंगलों में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिलासपुर, धर्मशाला, मण्डी व शिमला वृत में आग की अधिक घटनाओं की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च 2018 के बाद से प्रदेश भर में छोटी-बड़ी 641 वन अग्नि की घटनाएं घटी हैं।

वनमंत्री ने कहा कि इस वर्ष वन विभाग ने मार्च माह में वन अग्नि को लेकर प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके कारण इस वर्ष लोगों से वनों की आग बुझाने जैसे कार्यों में अधिक सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के फलस्वरूप इस वर्ष लगभग साढ़े नौ हजार व्यक्ति भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून की बेबसाइट से जुड़ चुके हैं, जिन्हें उनके क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाओं की सूचना मिल रही है। वन विभाग ने वन अग्नि सम्बन्धी सूचना देने के लिए एक टोल फ्री नं0 भी शुरू किया है। ऐसे ऐतिहाति उपायो से इस वर्ष गत वर्षों की अपेक्षा आग की सूचना तुरन्त सम्बन्धित कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों को मिल रही है। सूचना मिलने के कारण वन-अग्नि नियन्त्रण दस्ता तुरन्त वन अग्नि घटनास्थल तक पहुंच रहा है तथा स्थानीय लोगों के सहयोग सेवन अग्नि को जल्दी काबू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान वन अग्नि सम्बन्धी पूर्व-चेतावनियां भी दे रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों को पहले ही तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन कर्मियां को सूचना के आदान-प्रदान हेतु अप्रैल से जून माह तक के मोबाईल फोन भत्ता दिया जा रहा है तथा कर्मचारियों को आग बुझाने वाले क्षेत्र में शीघ्र पहुंचने के लिये टैक्सी का खर्चा अथवा निजी वाहन प्रयोग करने पर भ ा भी प्रदान किया जा रहा है।

वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में लगभग 400 फायर वाचर भी इस कार्य के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन अग्नि नियन्त्रण एवं प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय परियोजना में केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 1.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और इस वर्ष सेवन अग्नि प्रबन्धन हेतु प्रदेश सरकार ने नई परियोजना आरंभ की है, जिसमें वन अग्नि के प्रबन्धन कार्यो के लिए राज्य सरकार एक करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय करेगी।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार वन अग्नि के प्रति संवेदनशील है तथा ऐसी घटनाओं के कारण कम से कम क्षति हो, इसके लिए वन अधिकारियों को हर सम्भव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि तापमान में वृद्धि तथा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वन अग्नि की रोकथाम एवं नियन्त्रण में वन विभाग का खुले दिल से सहयोग करें।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को किया जाएगा सुदृढ़:पशुपालन मंत्री

शिमला/शैल। राज्य की आर्थिकी में पशुधन का बहुत बड़ा योगदान है और गांवों में अधिकांश किसानों के परिवारों की आजीविका काफी हद तक इसी पर निर्भर है। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा पशु पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने पशु पालन विभाग तथा हि.प्र. पशुधन और कुक्कुट विकास बोर्ड की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषकों के कल्याण के लिये कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि पशु पालन विभाग तथा हि.प्र. पशुधन और कुक्कुट विकास बोर्ड राज्य में पशुधन को बढ़ावा देने तथा इसके समुचित विकास के लिये मिलकर कार्य कर रहे हैं।

कंवर ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को सुदृढ़ किया

जाएगा। उन्होंने भ्रूण हस्तांतरण तकनीक पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पशु पालन कॉलेज पालमपुर भी विभाग तथा बोर्ड के साथ इस दिशा में मिलकर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि पशुधन के स्वास्थ्य तथा उत्पादन को अभिलेख व डाटा रखने के उद्देश्य से राज्य में पशु संजीवनी योजना को लागू किया जाएगा।

पशु पालन मंत्री ने कहा कि राज्य में ब्रॉयलर हैचरी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये सेक्स सार्टिड सिमन प्रयोगशालाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। इससे बछड़ियों की ही पैदावार होगी और दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि होगी।

विभाग के पशु पालन विभाग के प्रधान सचिव संजय गुप्ता, सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज डॉ. आर.एन. बत्ता तथा पशुपालन विभाग और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश के 2880 होटलो में से 1524 में अवैधताएं–पर्यटन विभाग के शपथ पत्र से सामने आया यह खुलासा

सरकार अभी तक भी नहीं कर पा रही है कोई कारवाई क्यों क्या कुछ मन्त्रीयों और अधिकारीयों का दबाब है

शिमला/शैल। प्रदेश में अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। कसौली गोली कांड के बाद तो कड़ाई की स्थिति एकदम बदल गयी है। अभी प्रदेश उच्च न्यायालय ने चिन्तपूर्णी मन्दिर को लेकर आयी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भरवांई से चिन्तपूर्णी तक सड़क के दोनों किनारों पर हुए अवैध निर्माणों और कब्जों पर एसडीएम अम्ब और देहरा से रिपोर्ट तलब की है और इन्हें हटाने के निर्देश दिये हैं। इसी के साथ इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों की भी जानकारी मांगी है।

कोई भी अवैधता एक दिन मे ही खड़ी नही हो जाती है और न ही यह संवद्ध तन्त्र की मिली भगत के बिना संभव होता है यह न्यायालय साफ कह चुके हैं। तन्त्र की इसी मिली भगत का प्रमाण रहा है कसौली कांड। जहां अदालत के फैसले पर अमल करवाने के लिये गये दो कर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ा है। इस कांड का जब सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया और इन अधिकारियों/कर्मियों को उपलब्ध करवाई गयी पुलिस सुरक्षा पर रिपोर्ट तलब की तब सरकार ने मण्डलायुक्त शिमला को इसकी जांच सौंपी। मण्डलायुक्त की रिपोर्ट में जब पुलिस की असफलता सामने आयी तब सरकार ने पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के खिलाफ कारवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया। इस निलम्बन में तत्कालीन एसपी भी शामिल हैं जब एसपी मौके पर वहां थे ही नही। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश मिलने के बाद डीसी सोलन ने इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये एसपी को निर्देश दिये थे। इन निर्देशों पर एसपी ने टीम गठित की थी। लेकिन इस टीम में जो प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार और एसडीएम थे क्या वह भी एसपी के निर्देशों पर आये थे या इसके लिये डीसी ने इन्हें तैनात किया था। यदि इसमें एसपी असफल रहे हैं तो क्या उसी तरह डीसी और उनके लोग भी असफल नहीं रहे हैं। पुलिस पर हुई कारवाई के बाद अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं।

कसौली के अवैध निर्माणों पर एनजीटी का 2017 मई में फैसला आ गया था। एनजीटी ने अपने फैसले में इन निर्माणों के लिये जिम्मेदार रहे कुछ अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये थे जिन पर आज तक अमल नही हुआ है। एनजीटी ने अपना फैसला देने से पहले प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट तलब की थी इसके लिये एक कमेटी बनी थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी की रिपोर्ट एनजीटी के फैसले में दर्ज है और यह रिपोर्ट भी फैसले का बड़ा आधार रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आ जाने के बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर फैसले का रिव्यू दायर किया गया है। क्योंकि जब तक रिव्यू का फैसला नही आ जाता है तब तक चिन्हित अधिकारियों के खिलाफ कारवाई से बचा जा सकता है।

इसी तरह जब कसौली को लेकर याचिकाएं चल रही थी तब प्रदेश उच्च न्यायालय में भी एक याचिका आयी जिसमें धर्मशाला और उसके आसपास हुए अवैध निर्माणों का प्रश्न उठाया गया था। इसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने अप्रैल 2017 में रिपोर्ट तलब की। इसी रिपोर्ट पर पर्यटन और प्रदूषण बोर्ड की सूचियों में अन्तर सामने आया। फिर से पूरे प्रदेश को लेकर रिपोर्ट तलब की गयी और अवैध रूप से चल रहे होटल अब तक सामने आ चुके थे उसके बिजली पानी के कनैक्शन काटने के आदेश किये गये। इस पर करीब 200 होटलों के बिजली पानी काटे गये लेकिन इसके बाद पूरे प्रदेश को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से दिसम्बर 2017 में जो शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर किया गया है उसके मुताबिक प्रदेश में 2880 होटल ईकाईयां पंजीकृत है और इनमें से 1524 में निर्माण से लेकर अन्य अवैधताएं पायी गयी हैं। पर्यटन विभाग के इस शपथ पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में आधे से ज्यादा होटल अवैध रूप से चल रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर जब यह अवैध होटल प्रदेश में चल रहे हैं तो यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज शेष बची है? क्या पूरी तरह अराजकता फैल चुकी है। इसमें सबसे दिलचस्प तो यह है कि विभाग अपने ही शपथपत्र में यह आंकड़ा उच्च न्यायालय के सामने रख रहा है लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से इन अवैधताओं के खिलाफ कोई कारवाई नही की जा रही है। इसमें भी उच्च न्यायालय के ही आदेशों की प्रतिक्षा की जा रही है। सूत्रों की माने तो होटल व्यवसाय में सरकार के कई मन्त्री भी प्रत्यक्षत:/अप्रत्यक्षत: शामिल हैं। मन्त्रीयों के अतिरिक्त कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और उनका सीधा प्रभाव मुख्यमन्त्री के कार्यालय तक है। इसी प्रभाव के कारण इन अवैधताओं के खिलाफ कारवाई करने का साहस नही हो पा रहा है।

धूमल ने खाली किया बंगला–राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चाओं का दौर शुरू

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल ने अन्ततः शिमला सरकारी आवास खाली कर दिया है। चुनाव हारने के बाद धूमल यह आवास खाली कर देना चाहत थे। लेकिन मुख्यमन्त्री के आग्रह पर उन्होनें ऐसा नही किया। सरकार ने धूमल के पीए से यह मकान रखने की अवधि बढ़ाने का आग्रह का पत्र मांगा और पीए ने दे दिया। इस पर सरकार ने केवल 31 मार्च तक समय बढ़ाया। 31 मार्च से पहले ही धूमल ने मकान खाली करने का फैसला ले लिया। इस फैसल की भनक लगते ही मुख्यमन्त्री ने फिर आग्रह किया। फिर समय बढ़ाने के लिये आग्रह पत्र लिया गया और इस पर केवल दो माह का समय बढ़ाया गया। इस तरह किश्तों में समय बढ़ाये जाने को अन्यथा लेते हुए धूमल ने अब मई समाप्त होने से पहले ही मकान खाली कर दिया।

धूमल के यह फैसला लेने के साथ ही संयोगवश यह भी घट गया की एक दिन उनके आवास पर पानी ही समाप्त हो गया। देर रात इसका प्रबन्ध हो पाया। इसी के साथ यह भी घटा कि जयराम सरकार जो केन्द्र की मोदी सरकार के चार साल पूरे होने का पीटर ऑफ में 26 मई को जश्न मनाने जा रही थी उसके लिये 25 तारीख रात तक धूमल को इसका आमन्त्रण ही नही दिया गया था। 25 तारीख शाम को भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और विधायक नरेन्द्र बरागटा तथा कुछ अन्य नेता धूमल से उनके आवास पर मिलने आये थे। शायद इन लोगों के माध्यम से सरकार तक यह सूचना पहुंची कि 26 तारीख के आयोजन के लिये धूमल को आमन्त्रण नही जा पाया है। इसलिये 26 मई को सुबह 10:30 बजे ही जयराम अपने कुछ सहयोगी मन्त्रीयों को लेकर उनके आवास पर पहुंच गये और उन्हें अपने साथ ले गये। 26 तारीख का आयोजन पार्टी का नही सरकार का था। पार्टी में जब इस पर चर्चा हुई थी तब यह तय किया गया था कि यह आयोजन प्रत्येक जिलास्तर पर किया जायेगा। लेकिन पार्टी का यह फैसला जयराम के कुछ सरकारी और गैर सरकारी सलाहकारों को रास नही आया। इसमें कुछ नौकरशाहों ने भी भूमिका निभाई और जिलों की बजाये इसे राज्य स्तर पर सीमित कर दिया। अब पार्टी अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। ऐसे में यदि यह आयोजन जिलास्तर पर होता तो इसका संदेश कुछ ज्यादा प्रभावी होता। यही नही इस आयोजन के जो विज्ञापन समाचार पत्रों को जारी किये गये हैं उनमें भी सरकार का रूख पक्षपात पूर्ण रहा है बल्कि बड़े सुनियोजित तरीके से प्रैस को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही प्रयास राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भी हुआ। ऐसा लगता है कि कुछ लोग बड़े ही सुनियोजित तरीके से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मीडिया को बांटकर रखा जाये ताकि मुख्यमन्त्री के सामने हरा ही हरा परोसा जाये और जमीनी हकीकत की जानकारी न होने दी जाये।

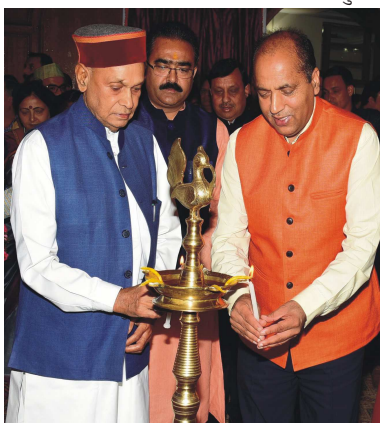

जयराम सरकार को सत्ता में पांच माह हो गये हैं। इस दौरान जिस तरह और जिस स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया गया है। उससे आज सचिवालय के गलियारों से लेकर सड़क तक यह चर्चा है कि जयराम की सरकार को तीन ही अधिकारी चला रहे हैं। इन अधिकारियों के साथ ही पत्रकारों का एक स्वार्थी टोला भी कुछ भूमिका निभा रहा है।जिसने धूमल को मकान खाली करवाने की स्थितियां पैदा कर दी जाने की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी जो सही भी साबित हुई है। क्योंकि किश्तों में मकान रखने का समय दिया जाना निश्चित रूप से धूमल के कद से मेल नही खाता है। इसी के साथ अब यह भी चर्चा में आ रहा है कि विभिन्न निगमों/बोर्डो में कार्यकर्ताओं की ताजपोशीयां भी एक योजना के तहत ही रोकी जा रही हैं। बल्कि यह भी कहा जाने लग पड़ा है कि जैसे वीरभद्र शासन में शिमला को ही हर जगह अधिमान दिया जाता था ठीक उसी तरह अब मण्डी को दिया जा रहा है। क्योंकि अब तक जो भी ताजपोशीयां हुई उनमें मण्डी का ही वर्चस्व रहा है।

भ्रष्टाचार के जितने मामलों का भाजपा के आरोप पत्रों में जिक्र किया गया है। उन पर अब बड़े सुनियोजित तरीके से प्रशासन यूटर्न लेता जा रहा है। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों पर यह सरकार भी उतनी ही गंभीर है जितनी की वीरभद्र सरकार थी। इससे यह संदेश जा रहा है कि भाजपा सत्ता पाने के लिये किसी पर भी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप लगा सकती है जो कि वास्तव में कहीं होता ही नही है या फिर सत्ता में आने पर उनको इन आरोपों से डराकर अपने स्वार्थो के लिये प्रयुक्त करती है। आज लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं और सरकार की विश्वसनीयता तथा कार्यकुशलता पर अभी से प्रश्नचिन्ह लगने शुरू हो गये हैं। यह सरकार अभी तक लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग के पद नही भर पायी है। फूड सिक्योरिटी कमीशनर को हटा तो दिया गया लेकिन उसकी जगह नयी नियुक्ति नही हो पायी है। इसी तरह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के भी दोनों पद खाली चल रहे हैं। इन सारे पदों का भरा जाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है जिस ओर कोई ध्यान ही नही जा रहा है। सरकार केवल अधूरे प्रशासनिक तबादले करने तक ही सीमित होकर रह गयी है।